जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 339 प्रभात उदयपुर, शुक्रवार 10 अक्टूबर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण हुई, पर इससे प्रश्न ज्यादा खड़े हुए उत्तर कम मिले

उदाहरण के लिए तीस लाख ऐसे वोटर हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, अब विधानसभा में वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया

-रेणू मित्तल---
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे, गठबंधन साझेदारों की मांगों और सीट समायोजन को लेकर अभी भी रस्साकशी जारी है।

कांग्रेस ने अपनी केन्द्रीय इलैक्शन कमेटी (सीईसी) की पहली और आखिरी बैठक की, जिसमें बताया गया कि लगभग 25 सीटों और उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कौन सी सीटें कांग्रेस को मिली हैं और कुल कितनी सीटें दी गई हैं।

इस बीच, गठबंधन के भीतर अब चर्चा इस बात की चल रही है कि महागठबंधन में तीन उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनका चयन जातीय संतुलन के आधार पर किया जाएगा।

- चुनाव आयोग के अनुसार, 21.53 लाख वोटर नये जुड़े हैं, पर इनमें से 16.93 लाख वोटर के ही ''फार्म 6'' उपलब्ध हैं, बाकी 4.6 लाख ''फार्म 6'' कहाँ गये, क्या यह वोटर बिना प्रक्रिया के ही जुड़ गये?
- नये वोटर में से दस प्रतिशत वोट केवल 15 एसेंबली सीटों में ही जोड़े गये हैं। अभी भी पाँच लाख डुप्लीकेट वोटर हैं, मतदाता सूची में, इनका शुद्धीकरण कैसे होगा।
- इस प्रक्रिया की जटिलता समझते हुए, लालू यादव अभी भी महागठबंधन की सीटों का बँटवारा फाइनल नहीं कर रहे हैं। वे अंतिम समय तक सबको लटकाये रखेंगे। अंतिम क्षणों में वो अपना फार्मूला प्रकट करेंगे, तब हताश होकर सभी घटक राजी होकर सीटों का बँटवारा स्वीकार कर लेंगे। चर्चा यह भी है कि यदि महागठबंधन सरकार सत्ता में आई तो जातिगत समीकरण को संतुष्ट करने के लिए तीन उपमुख्यमंत्री बनेंगे।

लालू प्रसाद यादव, जिन्हें गठबंधन राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, टिकट वितरण में सहयोगी दलों को आखिरी समय तक अनिश्चितता में रखने की कला में निपुण हैं, ताकि अंततः जब सीटें दी जाएं तो वे बिना विरोध स्वीकार कर लें। यह एक ऐसा खेल है, जिसमें लालू यादव हमेशा माहिर साबित हुए हैं।

हालांकि, चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप चाहे दीवार पर सिर मार लें चीख चिल्ला लें, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

दरअसल, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया और राज्य में आगामी चुनावों के लिए 7.42 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आयोग ने मशीन से, पढ़ने योग्य मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई, जिससे किसी भी तरह का विश्लेषण करना बेहद कठिन हो गया है।

इसके अलावा, आयोग ने मतदाता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हंगरी के लेखक को 2025 का नोबेल साहित्य सम्मान

स्टॉकहोम, 09 अक्टूबर। स्वीडिश अकादमी ने गुरुवार को हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक लास्लो क्रास्नाहॉरकाई को वर्ष 2025 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने के घोषणा की है। स्वीडिश अकादमी ने उनके नाम की घोषणा करते हुए बताया कि उन्हें यह पुरस्कार ''प्रलयकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुनः पुष्टि करने वाली प्रभावशाली और दूरदर्शी रचनाओं'' के लिए दिया जा रहा है।

क्रास्नाहॉरकाई समकालीन यूरोपीय साहित्य के उन लेखकों में गिने जाते हैं। वह विनाश की कहानियों में

- नोबेल विजेता लास्लो क्रास्नाहॉरकाई को उनकी विशिष्ट लेखन शैली के कारण ''प्रलय का शिल्पी'' भी कहा जाता है।

अस्तित्ववाद के साथ कल्पना को इस तरह मिश्रित कर देते हैं कि एक विचित्र एवं बेतुकी दुनिया पाठकों के सामने खड़ी हो जाती है, जो उन्हें झकझोर कर रख देती हैं। उनकी इसी विशिष्ट शैली के कारण मशहूर अमेरिकी आलोचक सुजैन सोनटेग ने उन्हें ''प्रलय का शिल्पी'' कहा था। लास्लो क्रास्नाहॉरकाई का जन्म 1954 में दक्षिण-पूर्वी हंगरी के छोटे से शहर ग्युला में हुआ था। वह अपनी कानून और साहित्य की पढ़ ई के साथ-साथ एक स्वतंत्र लेखक के रूप में भी काम करते रहे।

बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरु की चुनाव आयोग ने

बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष हैं, यह प्रक्रिया दो नवंबर से आरंभ होगी, तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीज़न -एसआईआर) के दौरान हुए विवादों और प्रशासनिक चूकों के बावजूद, चुनाव आयोग ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में इसी तरह की कवायद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं।

चुनाव आयोग ने एसआईआर से संबंधित सभी प्रारंभिक तैयारियों को पूरा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय की है, जबकि यह कवायद 2 नवंबर से शुरू होगी। इस प्रक्रिया के तहत, 15 करोड़ फॉर्म छापे जाएंगे, जो राज्य के 7.65 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को दिए जाएंगे। प्रत्येक मतदाता को दो प्रतियां दी जाएंगी - एक को बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को लौटाना होगा और दूसरी मतदाता अपने पास रखेगा।

बिहार में भारी विरोध झेलने के बाद, आयोग इस बार बेहद सतर्कता से कदम बढ़ा रहा है। चुनाव आयोग के

- चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार की गल्तियाँ बंगाल में नहीं दोहराई जाएं, इसके लिए प्रक्रिया में कई सुधार कर रहे हैं।
- पहली बात तो यह है कि बिहार में यह प्रक्रिया बहुत कम समय में पूर्ण की गई थी। अब चुनाव आयोग का दावा है कि प्रक्रिया की पूर्ति के लिए पूर्ण समय दिया जायेगा, जिससे तसल्ली से काम हो। साथ ही डिजिटल साधनों का वृहत् रूप से उपयोग किया जायेगा, जिससे समय की मारा मारी और कम हो।
- स्कूलों के अध्यापक-अध्यापिकाएँ, जो फार्म आदि भरने की मूल प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, ने भी हाथ खड़े कर दिये हैं कि उन्हें अध्यापन के कार्य से महीने भर की छुट्टी दिलाई जाए, क्योंकि वे अध्यापन और फार्म भरवाना दोनों काम एक साथ नहीं कर पायेंगे।

अधिकारियों का कहना है कि बिहार जैसी प्रशासनिक खामियों की पुनरावृत्ति न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय देने का निर्णय लिया है, जबकि बिहार में इसे बहुत कम समय-सीमा में पूरा किया गया था।

मैनुअल प्रविष्टियों में लगने वाले समय को कम करने और समग्र दक्षता के बढ़ाने के लिए, आयोग डिजिटल उपकरणों का उपयोग करेगा, जिनसे ''वन-क्लिक अपलोड'' की सुविधा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीजेआई पर हमला करने वाले राकेश किशोर की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस पर बैन

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एडवोकेट राकेश किशोर की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले अधिवक्ता राकेश किशोर (71) की अस्थायी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है और उन्हें ''गंभीर दुर्व्यवहार'' का दोषी ठहराया है।

एसीसीबीए द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि सदस्य संख्या के-01029/ आरईएस दिनांक 27.07.2011 वाले राकेश किशोर की सदस्यता ''तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है और उनका नाम एसोसिएशन की सूची से हटा दिया जाएगा।''

- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए राकेश किशोर के घोर निंदनीय तथा अनुशासनहीन व्यवहार की कड़ी आलोचना की।
- बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने भी राकेश किशोर की सदस्यता रद्द कर दी।
- सूत्रों ने बताया कि 71 वर्षीय राकेश किशोर के खिलाफ फौजदारी अवमानना की कार्यवाही शुरु करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक न्यायालय के अधिकारी (आफिसर ऑफ द कोर्ट) का ऐसा ''घृणित, अव्यवस्थित और असंयमित व्यवहार'' अनुचित और बार के सदस्यों से अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव में आगे कहा गया कि यदि किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता कार्ड जारी किया गया है तो वह ''तुरंत रद्द और जब्त'' किया जाता है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह संदेश भेजा जाएगा कि उनका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रशांत किशोर ने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। पीढ़ियों से गणित की पाठ्यपुस्तकें लिखने वाले गणितज्ञ, पूर्व नौकरशाह, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और डॉक्टर, ये सब उन 51 उम्मीदवारों में शामिल हैं, जिनकी घोषणा आज दोपहर प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी ने की। यह बिहार में अगले महीने

- इनमें 16 प्रतिशत मुसलमान तथा 17 प्रतिशत अतिपिछड़ा वर्ग से हैं।

होने वाले दो चरणों के चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी की पहली सूची है।

पहली सूची में 16 प्रतिशत उम्मीदवार मुसलमान हैं और 17 प्रतिशत अति पिछड़ी जातियों से आते हैं। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। इसलिए उम्मीदवारों के चयन में उनकी स्वच्छ छवि को प्रमुख मानदंड बनाया गया। किशोर ने चुनावी मुकाबले के लिए कई पूर्व नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को भी उम्मीदवार बनाया है।

'अपने सामान के साथ पासपोर्ट ही नहीं बल्कि खूब सारा धैर्य भी पैक करें'

अमेरिका जाने वाले यात्रियों को अब अनुभवी ट्रैवेल एजेंट्स यह नेक सलाह दे रहे हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर निकलने वाले यात्रियों के लिए अव्यवस्था का सामना करना आम बात हो गई है। सातवें दिन में पहुंच चुके संघीय सरकार के शटडाउन (कामकाज बंदी) का असर अब वॉशिंगटन के राजनीतिक गतिरोध से कहीं आगे फैल चुका है -उड़ानों में बाधा, राष्ट्रीय उद्यानों पर दबाव, और छुट्टी पर होने वाली हजारों यात्राओं को अनिश्चितता में डाल दिया है। यह स्थिति एक अक्टूबर से तब शुरू हुई जब सांसद नई वित्तीय योजना पर सहमत नहीं हो पाए। इसके परिणामस्वरूप सरकार के बड़े हिस्से ठप हो गए हैं - लगभग 40 प्रतिशत संघीय कर्मचारी, यानी करीब 7.5 लाख लोग, बिना वेतन छुट्टी पर भेजे गए हैं।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था की धुरी माना जाने वाला उड्डयन उद्योग इस संकट का शुरुआती शिकार बन गया है।

- एक अक्टूबर से अमेरिकी सरकार में लागू शटडाउन में केवल आवश्यक सेवाएँ ही कार्यरत हैं, क्योंकि इन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मनचाही छुट्टी जाने का अधिकार नहीं है। यह कर्मचारी बिना तनख्वाह के दस-दस घंटे काम कर रहे हैं।
- इससे सभी सेवाएँ प्रभावित हुई हैं और सबसे ज्यादा हवाई यात्रा।
- इन कर्मचारियों की लंबी थकान से फ्लाइट सुरक्षा प्रभावित हो रही है। एक विशेषज्ञ के अनुसार, एयर ट्रैफिक बारीकी (प्रिसिशन) व मनोबल से चलता है और आप अनिश्चितता के वातावरण में काम कर रहे कर्मचारियों से, जिन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रही, उतनी कार्यकुशलता की अपेक्षा नहीं कर सकते। फ्लाइट्स असुरक्षित ही नहीं, विलंबित भी होती जा रही हैं।

हवाई यातायात नियंत्रक (एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स), जिन्हें ''जरूरी कर्मचारी'' घोषित किया गया है, उन्हें बिना वेतन काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब थकान के संकेत दिखने लगे हैं। सोमवार, 6 अक्टूबर को, न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस के प्रमुख हवाई अड्डों पर स्टाफ की कमी के कारण 6,000 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं। लॉस एंजेलिस का हॉलीवुड बरबैंक एयरपोर्ट तो अस्थायी रूप से बंद करना पडा क्योंकि सुरक्षा मानक बनाए रखना संभव नहीं था।

नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन (एनएटीसीए) ने कड़ा चेतावनी संदेश जारी करते हुए कहा है कि यह संकट ''आधुनिकीकरण की गति को धीमा कर सकता है'' और ''पूरे उड्डयन तंत्र की विश्वसनीयता और दक्षता को खतरे में डाल सकता है।'' संगठन के अध्यक्ष, रिच सैंटा ने कहा, ''कंट्रोलर्स से हफ्ते में 6 दिन दस-दस घंटे, काम करने को कहा जा रहा है - वो भी बिना वेतन। पिछली बार के शटडाउन में कई लोगों को परिवार का पेट पालने के लिए दूसरी नौकरी करनी पड़ी थी। ऐसे तनाव सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है।

फिर भी, कुछ मजबूती अब भी बनी हुई है। सिरियम नामक एविएशन एनालिटिक्स कंपनी के अनुसार, मंगलवार दोपहर तक अमेरिकी हवाई अड्डों से रवाना होने वाली 23,600 उड़ानों में से 92 प्रतिशत समय पर रवाना हुईं। लेकिन विश्लेषकों का कहना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को वादा किया कि राज्य के हर घर को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह वादा किसी

- तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा की और कहा, बिहार में कोई घर बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा।

भावनात्मक आधार पर नहीं, बल्कि आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि यदि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आता है, तो राज्य के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सरकारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो साल की बेरहम लड़ाई से तंग आकर अरब देशों ने शांति प्रस्ताव स्वीकार किया?

जैसा कि विदित ही है, इस लड़ाई में साठ हज़ार फिलिस्तीनी मारे गये थे और अंततोगत्वा फिलिस्तीनी भी हमास की इज़रायल से लगातार युद्ध की नीति से हताश हो गये हैं

-अंजल रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। इज़रायलियों की एक निहत्थी यहूदी बस्ती में हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए अपहरण और हत्या के बाद शुरू हुए इक्कीसवीं सदी के इस कुरुक्षेत्र में लगभग 60,000 गाज़ावासियों की मौत के साथ, अब यह ''युद्ध'' समाप्ति की ओर बढ़ता दिख रहा है।

आख़िरकार, गाज़ा में इज़रायल का गाज़ा में युद्ध खत्म होने जा रहा है। इस लंबे संघर्ष की भारी मानवीय और आर्थिक कीमत देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब अरब जगत इज़रायल के अस्तित्व को सामान्य और स्थायी रूप में स्वीकार करेगा और इज़रायल भी निरंतर टकराव की निरर्थकता को समझेगा।

जैसे ही इज़रायल की सरकार गाज़ा में युद्ध समाप्त होने की घोषणा करेगी, उग्रवादी संगठन हमास अपने कब्जे में रखे सभी इज़रायली बंधकों को रिहा कर देगा। मारे गए बंधकों के शव भी इज़रायल को सौंपे जाएंगे।

इसके बदले में, इज़रायल अपनी जेलों में बंद लगभग 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, उनके नामों पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। तथापि, इज़रायल ने स्पष्ट किया है कि जिन कैदियों को हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया है, उन्हें गाज़ा प्रशासन को नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि किसी तीसरे देश में भेजा जाएगा।

7 अक्टूबर के हमले के मुख्य सूत्रधार यह्या सिनवार और उनके भाई

- क्या अरब देशों ने अब इज़रायल के अस्तित्व को सामान्य व गैर तब्दील हो सकने वाला तथ्य मान लिया है।
- यह स्वीकार हो जाने के बाद इज़रायल के पास भी अब अरब देशों से लड़ने का कोई कारण नहीं बचा है।
- शांति प्रस्ताव की बाकी बारिकियाँ अभी तये हो रही हैं, पर प्रमुख बात यह है कि हमास अब तमाम इज़रायली बंधकों को रिहा करेगा और मृत बंधकों के शरीर भी इज़रायल को सौंपेगा। इज़रायल भी ढाई सौ फिलिस्तीनी, जो उसकी कैद में हैं, को छोड़ेगा। केवल उन कैदियों को जिन पर हत्या का आरोप है, उन्हें सीधे फिलीस्तीनियों को नहीं देगा, बल्कि किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करेगा। शांति वार्ता मिस्र की सीमा के पास हॉलिडे रिसॉर्ट शर्म अल शेख में हुई थी तथा तुर्की भी समझौते की बारिकियों को तय करने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा था।

मोहम्मद सिनवार, जो यह्या की इज़रायल द्वारा हत्या के बाद हमास के नेता बने थे, के शव नहीं सौंपे जाएंगे।

हमास और फिलिस्तीनी पक्ष ने अमेरिका द्वारा तय की गई शर्तों और अमेरिकी गारंटी पर आधारित इस समझौते को स्वीकार कर लिया है।

युद्धरत पक्षों के बीच तनाव कम होने के बाद, गाज़ा का प्रशासन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक समूह करेगा, जो इसके पुनर्निर्माण और पुनर्वास की निगरानी करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रत्यक्ष नेतृत्व में काम करने के लिए एक ''बोर्ड ऑफ पीस'' (शांति परिषद) के गठन की वकालत की थी।

इस बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे, जिन्होंने मध्य पूर्व में अपने कार्यकाल के बाद से शांति प्रक्रिया पर व्यापक रूप से काम किया है। इसके अलावा, मध्य पूर्व के कुछ प्रमुख देशों के प्रतिनिधि भी गाज़ा के प्रशासन और पुनर्निर्माण में भाग लेंगे।

शांति समझौते के पहले चरण को स्वीकार किए जाने की घोषणा के बाद, इज़रायल और गाज़ा तथा फिलिस्तीन,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसएमएस में न्यूरो सर्जरी का एचओडी रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, 9 अक्टूबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जयपुर मुख्यालय की एसआईयू टीम ने गुरुवार की रात को कार्रवाई करते हुए सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के

- डॉ. मनीष अग्रवाल एसएमएस मैडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल भी हैं।

अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत सिग्नेचर करने के एवज में मांगी गई थी। फिलहाल एसीबी उनके आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ले रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)